भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2274
19/12/2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि से किसानों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान

2274. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि से किसानों की प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों की कृषि से होने वाली औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय का सटीक अनुमान लगाने हेतु मिशन मोड में कोई सर्वेक्षण करवाएगी, ताकि उनकी समस्याओं के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके और उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पुराने और अप्रचलित आंकड़ों का प्रयोग करने और 65 प्रतिशत आबादी के आत्महत्या करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार, केंद्रीय स्तर पर किसानों की प्रति व्यक्ति आय का कोई डेटा संग्रहित नहीं करती है। तथापि, देश में कृषि परिवारों (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा परिभाषित) की औसत मासिक आय का अनुमान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित "कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से समय-समय पर किया जाता है। नवीनतम एनएसएस सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह है। कृषि वर्ष जुलाई 2018-जून, 2019 के लिए राज्यवार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय **अनुबंध I** में दी गई है।

(ग) से (ङ): भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। पारिवारिक उपभोग व्यय पर एनएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में 2011-12 (68वें दौर) के अनुमानों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमपीसीई की तुलना प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यय स्तरों में वृद्धि और इस अवधि के दौरान संबंधित वृद्धि प्रतिशत को दर्शाया गया है।

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)		वृद्धि (%)
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-24	
ग्रामीण	1, 430	4, 122	188.2
शहरी	2, 630	6, 996	166.1

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक नीतियां, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएं अपनाई और लागू की हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। इन योजनाओं में कृषि के सभी क्षेत्र, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से कम से कम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिलाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध II** में दी गई है।

अनुबंध-I

कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/ संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	आय (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	10,480
2	अरुणाचल प्रदेश	19,225
3	असम	10,675
4	बिहार	7,542
5	छत्तीसगढ़	9,677
6	गुजरात	12,631
7	हरियाणा	22,841
8	हिमाचल प्रदेश	12,153
9	जम्मू एवं कश्मीर	18,918
10	झारखंड	4,895
11	कर्नाटक	13,441
12	केरल	17,915
13	मध्य प्रदेश	8,339
14	महाराष्ट्र	11,492
15	मणिपुर	11,227
16	मेघालय	29,348
17	मिजोरम	17,964
18	नागालैंड	9,877
19	ओडिशा	5,112
20	पंजाब	26,701
21	राजस्थान	12,520
22	सिक्किम	12,447
23	तमिलनाडु	11,924
24	तेलंगाना	9,403
25	त्रिपुरा	9,918
26	उत्तराखंड	13,552
27	उत्तर प्रदेश	8,061
28	पश्चिम बंगाल	6,762
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**16,863**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**18,511**
	अखिल भारतीय	**10,218**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587*: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भू-धारित और पशुधन की स्थिति का आकलन, 2019*

अनुबंध-II

किसानों के कल्याण के लिए उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करने और आय में सहायता उद्देश्यार्थ प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

*****